

फिर से जोखिम : आरबीआई और वैश्विक अनिश्चितताएं बढ़ने का सवाल

द हिंदू

पेपर-III (भारतीय अर्थव्यवस्था)

भू-राजनैतिक तनावों, आर्थिक विखराव, अस्थिर वित्तीय बाजारों और असमान मानसून के जोखिमों के बीच, 6 अक्टूबर को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) इस वित्तीय वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 6.5 फीसदी की वृद्धि, जिसे घरेलू मांग को मजबूत करके समान रूप से संतुलित किया गया है, के अपने अनुमान पर अडिग रहा। ऐसी धारणा थी कि बढ़ी हुई अनिश्चितताओं का दौर खत्म हो रहा है, लेकिन केंद्रीय बैंक के गवर्नर द्वारा पिछले शुक्रवार को दिए गए संकेतों के मुताबिक ही पिछले एक पखवाड़े से नई अनिश्चितताएं उभरकर सामने आई हैं। मौद्रिक नीति समीक्षा के एक दिन बाद शुरू हुआ इजराइल-हमास संघर्ष और व्यापक हो गया है तथा वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वैश्विक स्तर पर खाद्य, ईंधन और उर्वरकों की आपूर्ति पर इसके प्रभाव को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। ईंधन और उर्वरकों के आयात पर भारत की निर्भरता को देखते हुए, भले ही सरकार इस चुनावी मौसम में उपभोक्ताओं और किसानों के सिर पर उच्च कीमतों का बोझ सरकारने से बच रही हो लेकिन कोई भी व्यवधान या कीमतों में वृद्धि वृहद-आर्थिक ढांचे को नुकसान पहुंचा सकती है। आरबीआई के मुखिया ने बढ़ती अमेरिकी बंध पत्र आय (बांड यील्ड) की ओर भी इशारा किया, जो इस सप्ताह 16 साल के उच्चतम स्तर पांच फीसदी पर पहुंच गई। दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों से मिलने वाले मिश्रित डेटा बिंदुओं और संकेतों से नए अज्ञात पहलू- यहां तक कि वित्तीय बाजार में होने वाले उथल-पुथल जैसे जाने-पहचाने अज्ञात पहलू भी और ज्यादा स्पष्ट हो गए हैं। इस चिंता की झलक इस सप्ताह दिखाई दी, जब जुलाई के बाद से भारतीय बाजारों में सबसे तेज बिकवाली हुई।

इस बात को लेकर कोई निश्चितता नहीं है कि आरबीआई अभी भी विकास के जोखिमों के प्रति अपने 'समान रूप से संतुलित' दृष्टिकोण को बरकरार रखेगा। हालांकि इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि वैश्विक अनिश्चितताएं बढ़ गई हैं, वित्त मंत्रालय अर्थव्यवस्था से जुड़े अपने दृष्टिकोण को लेकर फिलहाल काफी हद तक आशावादी नजर आता है। सोमवार को जारी इसकी मासिक आर्थिक समीक्षा में यह दावा किया गया है कि विकास "पटरी पर बना हुआ है", जुलाई-अगस्त में "अस्थायी" मौसमी उछाल के बाद मुद्रास्फीति कम हो रही है, उपभोग की मांग मजबूत हो रही है और निवेश संबंधी मांग भी "बढ़ रही है"। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों की "आसन्न आशंकाओं" के बारे में, यह दर्ज किया गया कि जुलाई-सितंबर तिमाही की कीमतें अभी भी 2022-23 की पहली और दूसरी तिमाही के क्रमशः 109.5 अमेरिकी डॉलर और 97.9 अमेरिकी डॉलर के औसत से "काफी कम" थीं। इसमें कहा गया है कि जहां कमजोर विदेशी व्यापार की तस्वीर ठीक होने की उम्मीद है और अगली दो तिमाहियों के दौरान औद्योगिक रोजगार सृजन की संभावनाएं अधिक हैं, वहीं आवास एवं वाहन ऋण की उच्च मांग परिवारों में बढ़े हुए आत्मविश्वास के स्तर को दर्शाती है। भारत के 'मैक्रो फंडामेंटल्स' ताजा वैश्विक झंझावातों के बावजूद अच्छी तरह से कायम रह सकते हैं, लेकिन सरकार के लिए उपभोग और नियुक्ति के रुझानों पर थोड़ा गहराई से विचार करना अच्छा होगा। पिछली तिमाही में छोटी कारों की बिक्री में भारी गिरावट देखी गई है, गैर-टिकाऊ उपभोक्ता सामानों के उत्पादकों ने कमजोर ग्रामीण मांग की खबर दी है और आईटी कंपनियों ने विकास दर एवं भर्ती की उम्मीदों को कम कर दी हैं। उबरने की असमान प्रक्रिया, जो आखिरकार व्यापक निवेश के फिर से शुरू होने में बाधा पैदा करेगी, को दुरुस्त करने के लिए अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

संभावित प्रश्न (Expected Question)

प्रश्न : निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. आरबीआई ने इस वित्तीय वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 6.5 फीसदी की वृद्धि के अपने अनुमान को परिवर्तित कर दिया है।
2. अमेरिकी बांड यील्ड पिछले डेढ़ दशक में सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

Que. Consider the following statements-

1. RBI has changed its estimate of growth in gross domestic product (GDP) to 6.5 percent for this financial year.
2. US bond yields have reached the highest level in the last one and a half decade.

Which of the statements given above is/are correct?

- (a) Only 1
- (b) Only 2
- (c) Both 1 and 2
- (d) Neither 1 nor 2

उत्तर : b

संभावित प्रश्न व प्रारूप (Expected Question & Format)

प्रश्न : “भारत के ‘मैक्रो फंडामेंटल्स’ ताजा वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद अच्छी तरह से कायम रह सकते हैं, लेकिन सरकार के लिए उपभोग और रोजगार सृजन पर थोड़ा गहराई से विचार करना लाभकर होगा।” टिप्पणी कीजिए।

उत्तर का दृष्टिकोण:

- ❖ उत्तर के पहले भाग में भारत के ‘मैक्रो फंडामेंटल्स’ की स्थिति और वर्तमान वैश्विक अनिश्चितताओं की भारतीय अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभावों की चर्चा करें।
- ❖ दूसरे भाग में सरकार के द्वारा उपभोग और रोजगार सृजन पर क्या प्रयास करने की आवश्यकता है, उसकी चर्चा करें।
- ❖ अंत में आगे की राह दिखाते हुए निष्कर्ष दें।

नोट : अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।